भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2305

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

सूक्ष्म उद्यमों हेतु क्रेडिट कार्ड

†2305. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को पांच लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए एक अनुकूलित क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत जारी किए गए क्रेडिट कार्डों की राज्य-वार संख्या कितनी है और कुल कितना ऋण स्वीकृत और संवितरित किया गया है;

(ग) क्या प्रथम वर्ष में दस लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो लक्ष्य पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों का समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 25 मई 2026 को किया गया है। योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ₹5 लाख तक की ऋण सीमा
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत गारंटी कवरेज
- कोई संपार्श्विक आवश्यक नहीं है
- योजना के अंतर्गत शुरुआती 10 लाख ग्राहकों के लिए जारी किए गए प्रति रुपे कार्ड पर अधिकतम 500 रुपये तक का प्रवेश शुल्क माफ किया जाएगा।

(ख) और **(ग)**: इस योजना का शुभारंभ हाल ही में हुआ है। 20 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार**,** योजना के अंतर्गत 12,398 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं**,** जिनकी कुल संस्वीकृत राशि 136.91 करोड़ रुपये है**,** और राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ): इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित देश में सभी उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम पात्र हैं।

*****

अनुबंध

दिनांक 03.08.2026 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2305 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

20 जुलाई, 2026 तक योजना के अंतर्गत जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए कार्डों की संख्या	स्वीकृत ऋण सीमा (लाख रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	0.81
2	आंध्र प्रदेश	658	873.32
3	अरुणाचल प्रदेश	6	8.91
4	असम	244	285.06
5	बिहार	733	921.67
6	चंडीगढ़	63	75.24
7	छत्तीसगढ़	84	73.15
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	6	12.70
9	दिल्ली	276	354.76
10	गोवा	57	66.58
11	गुजरात	496	587.27
12	हरियाणा	501	479.70
13	हिमाचल प्रदेश	140	119.59
14	जम्मू और कश्मीर	72	66.77
15	झारखंड	541	346.51
16	कर्नाटक	515	825.82
17	केरल	256	311.68
18	लद्दाख	1	1.35
19	मध्य प्रदेश	551	511.43
20	महाराष्ट्र	1,259	1,482.22
21	मणिपुर	8	11.10
22	मेघालय	6	16.28
23	मिजोरम	6	6.14
24	नागालैंड	8	16.05
25	ओडिशा	441	440.08
26	पुडुचेरी	20	21.38
27	पंजाब	822	877.73
28	राजस्थान	565	509.40
29	सिक्किम	6	4.60
30	तमिलनाडु	1,121	1,399.77
31	तेलंगाना	275	416.69
32	त्रिपुरा	31	24.69
33	उत्तर प्रदेश	1,678	1,661.42
34	उत्तराखंड	242	205.61
35	पश्चिम बंगाल	708	675.55
	कुल	**12,398**	**13,691.05**

स्रोत: पीएसबी एलायंस